

Request to provide drinking water to Jalore Sirohi and Badmer from Mahi and Kadana Dam

श्री लुम्बा राम (जालौर) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ ।

महोदया, सिरौही जालौर में पिछले कई सालों से भू-जल स्तर में भारी गिरावट के कारण दोनों जिले डार्क जोन घोषित हो चुके हैं । इस क्षेत्र के किसानों को डार्क जोन से मुक्ति दिलाने हेतु माही बांध का पानी सिरौही जालौर जिले के लिए उपलब्ध कराएं । यह योजना 60 वर्षों से बनी हुई है, जिसे कांग्रेस सरकार ने कागजों में दफन कर रखी थी । ऐसे में किसानों की उम्मीदें भी टूट गई थीं। मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र जी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को पेयजल और सिंचाई के पानी को लेकर फिर उम्मीद जगी हैं ।

आपसे निवेदन है कि वर्ष 1966 में राजस्थान सरकार व गुजरात सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार माही बांध परियोजना का कार्य शुरू हुआ था । उस समय खोंसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितम्बर 1965 के अनुसार गुजरात राजस्थान के बीच बोर्डर पर कडाणा बांध बनाना प्रस्तावित था । उस समय 01 अक्टूबर 1966 को राजस्थान एवं गुजरात सरकार के बीच माही जल बंटवारा समझौता में कडाणा बांध का निर्माण हुआ था । उस समझौते के अनुसार, खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी आने के बाद कडाणा और माही बांध के पानी का 2/3 हिस्सा राजस्थान को और गुजरात के खेड़ा जिले को 1/3 पानी मिलना तय हुआ था ।

चूंकि वर्ष 2005 में नर्मदा का पानी गुजरात के खेड़ा जिले को मिल रहा है, तो अब समझौते के अनुसार जालौर सिरौही को अपने हक का पानी मिलना चाहिए । मुझे यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के हक का पानी कडाणा बांध से पिछले 37 वर्षों में 27 बार ओवरफ्लो होकर 1.30 लाख एम सी एम पानी समुद्र में बह गया ।

अतः पूरे पश्चिमी राजस्थान के किसानों की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुसार किसानों के हित में कडाणा व माही बांध के पानी के लिए हाई लेवल नहर के माध्यम से, जालौर सिरौही व बाडमेर के गावों में पेयजल हेतु माही व कडाणा का पानी उपलब्ध कराएं ।

मेरा पुनः निवेदन है कि यह योजना समय पर लागू करें । इसके लिए पश्चिमी राजस्थान का किसान वर्ग और जालौर सिरौही के किसान आपके आभारी रहेंगे ।